मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- अमित शाहः भारत का नया जनरल डायर
- संघ-भाजपा का संगठन मंथन — 3

- नीतीश को माफ़िया की चुनौती : लोकतंत्र या अपराधतंत्र — 4

- न कालीघाट में काली मिले .....बिना सेटिंग के
- पूंजीपतियों का गुलाम वकील अरुण जेटली — 5

- ईएसआईसी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हो
- थाने-चौकियों में लगने की होड़, क्राइम बढ़ता ताबड़तोड़ — 8

वर्ष 29 अंक 21 फरीदाबाद, शुक्रवार16-30 सितम्बर 2016 फोन : - 9999595632 ₹ 2

चौटाला की जारी जेल पारी, हुड्डा की हो रही तैयारी

लुटेरे मन्त्रियों के रहते क्या खट्टर बचा पायेंगे अपनी बारी ?

हरियाणा की मनोहरलाल सरकार बीफ़ बीरयानी पकड़ने के अभियान में इस कदर व्यस्त हैं कि उसे इस बार एचसीएस नियुक्तियों में सिफ़ारिश और पैसा चलाने का समय ही नहीं मिला। यह तो हुई मज़ाक की बात। दरअसल, बीसियों साल में पहली बार एचसीएस के नतीज़ों में सामान्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का चयन हुआ है और सत्ता के रसूख वाले व रुपयों की थैली खर्चने वाले रह गये। इसका श्रेय मुख्यमंत्री खट्टर को ही दिया जायेगा। हालांकि तमाम भाजपाई व संघी मुंह फुलाये घूम रहे हैं। क्या हरियाणा में सरकारी नौकरियां देने में नये युग की शुरुआत हो रही है? चौटाला की जेल पारी चल रही है; हुड्डा की तैयारी हो रही है; सवाल है खट्टर की बारी तक क्या होगा?

मज़दूर मोर्चा, चंडीगढ़ ब्यूरो

करीब पांच वर्ष पूर्व जब शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटालों को सज़ा हुई थी, 'मज़दूर मोर्चा ने लिखा था कि चौटालों को जेल जाते देख मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भले ही खुश हो रहे होंगे और मान रहे होंगे कि वे तो बहुत सयाने हैं, कभी पकड़ में नहीं आयेंगे, परन्तु जेल यात्रा उनकी भी शुरू होने वाली है। अब वह वक्त आ गया है। बतौर प्रोपर्टी डीलर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने सत्ता का दुरूपयोग करके जिस तरह किसानों की

ज़मीनें छीनी थी, वे सारे घोटाले अब सामने आने लगे हैं।

हुड्डा ने अपनी ओर से बेशक पूरी होशियारी बरतते हुए उन ज़मीनों पर भूमि अधिग्रहण की धारायें 4,6, व 9 आदि लगाई जो बिल्डरों को चाहियें थीं। ये धारायें लगाना कोई जुर्म नहीं। कुछ समय पश्चात् हुड्डा ने उक्त धारायें हटा कर उन ज़मीनों को अधिग्रहण से मुक्त भी कर दिया। कानून की दृष्टि में यह भी कोई जुर्म नहीं बनता। लेकिन उक्त धारायें लगाने व हटाने के बीच जो हज़ारों करोड़ का खेल हो गया उसने इस सारी कवायद को धोखा धड़ी व सत्ता के दुरूपयोग का जुर्म बना दिया।

ज़िला सोनीपत व गुड़गांव आदि में हुड्डा ने अपने चहेते बिल्डरों को ज़मीने दिलाने की नीयत से उक्त धारायें लगाई थीं। जो किसान किसी भी कीमत पर बिल्डरों को अपनी ज़मीने नहीं बेचना चाहते थे, वे अधिग्रहण की धारायें लगाने के बाद बिल्डरों के चंगुल में फ़ंस गये। बिल्डरों ने किसानों को अधिग्रहण के सरकारी दामों से कहीं अधिक दाम देकर ज़मीने खरीद लीं। बिल्डरों के सौदे पक्के हो जाने के बाद हुड्डा ने उन ज़मीनों का सीएलयू बदल कर खेती से रिहायशी व व्यवसायिक भी कर दिया। यदि यही सीएलयू हुड्डा साहब पहले कर देते तो इसका लाभ किसानों को मिलता; परन्तु उससे हुड्डा को क्या मिलता? कुछ नहीं। माल तो बिल्डरों से मिलना था जो मिल गया नकद। हुड्डा को मिला भारी कमीशन। कब से यह धोखाधड़ी पूरी तरह नंगी थी, अब कानून की हिलजुल हुयी है।

हालांकि हुड्डा के अन्य कारनामों को देखते हुए कानून की यह हलचल अधूरी ही कही जायेगी। अगर गहराई से हुड्डा के जमाने में सम्पन्न हुई भर्तियां भी जांच का विषय बनाई जाये तो तमाम घोटाले सामने आयेंगे। अपने पूर्ववर्ती औम प्रकाश चौटाला की तर्ज पर हुड्डा ने भी अपनी चिटों व सूचियों की माफ़र्त ही भर्तियां होने दी थीं। क्या एचसीएस, क्या अधीनस्थ सेवा बोर्ड और क्या पुलिस-हर भर्ती का यही हाल था। पुलिस की लिस्टें तो तत्कालीन सीआईडी चीफ़ परमवीर राठी के दफ़्तर में फ़ाइनल होती थी। रिटायर होने के बाद राठी साहब हुड्डा के पुलिस एडवाइज़र बन गये। उनका दफ़्तर भी वही रहा और भर्ती की लिस्टें भी वैसे ही बनती रहीं।

फ़िलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अपना काम काज ईमानदाराना है। पर यही बात उनके मन्त्रियों, विशेष कर रामबिलाश शर्मा और कैप्टेन अभिमन्यु के लिये नहीं कही जा सकती जो कि चौटाला और हुड्डा के नक्शे कदम पर चलने को बेताब नज़र आते हैं।

कितने आरएसएस ?

एक आरएसएस से तो सभी परिचित हैं। यह मोहन भागवत की आरएएस है जिसे हिन्दुत्व, लव जिहाद, बीफ़ हत्या, दलित उत्पीड़न, मुस्लिम-ईसाई नफ़रत, हिन्दू स्त्रियां 10-10 बच्चे पैदा करें, जैसी बातों के लिये जाना जाता है। पिछले दिनों में तीन और आरएसएस से इस देश की जनता का साक्षात्कार हुआ है।

पहला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक रामदेव। यह व्यक्ति अपने माल के विज्ञापनों में दावा करता है कि 80 से 90 प्रतिशत दूध व शत प्रतिशत सरसों का तेल मिलावटी बिक रहा है। यही नहीं तमाम अन्य खाद्य पदार्थ और ब्यूटी प्रोडेक्ट में बेहद खतरनाक कैमिकल मिले होते हैं। समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार जानबूझ कर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों होने दे रही है? या तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक रामदेव झूठा और फ़रेबी है या राष्ट्रवादी मोदी सरकार निकम्मी और जनविरोधी है।

दूसरा है रिलायंस स्वयं सेवक। यह कोई और नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं हैं। पिछले दिनों इनके बड़े-बड़े फ़ोटो मुकेश अम्बानी के रिलायंस जीओ विज्ञापनों की शोभा बढ़ाते देखे गये। लगता है भारत सरकार का डिजिटल इन्डिया प्रोग्राम मुकेश अम्बानी के कंधों पर सवारी करने को मजबूर है। एक तरह से रिलायंस स्वयं सेवक मोदी यही तो कह रहे हैं कि देश को रिलायंस ही चला रहा है।

तीसरे हैं रेल स्वयं सेवक सुरेश प्रभु। इन्होंने देश की सेवा में रेल को 'आधुनिक' बनाने का और सन् 2020 तक हर सम्भावित यात्री को पक्की टिकट (सीट) उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया हुआ है। इस क्रम में पहले वे एक लाख करोड़ की एक बुलेट ट्रेन लाये, बेशक ट्रेन और पटरियों का अकाल ज्यों का त्यों बना रहे। अब उन्होंनें फ्लेक्सी किराया शुरू किया है जिसके अन्तर्गत हर 10 प्रतिशत सीट बिकने के बाद किराया स्वत: बढता जायेगा। वैसे प्रभु को 20 20 तक इन्तज़ार करने की भी क्या जरूरत है? यदि वे आज ही किराया दस गुणा बढ़ा दें तो ज़्यादातर लोग रेल यात्रा करना वैसे ही बंद कर देंगे और तब सीटें लेने वाला कोई विरला ही मिलेगा।

उम्मीद है ये तीनों आरएसएस, भागवत की आरएसएस के साथ मिल कर राष्ट्र को 'विकास' की नई मंजिलों पर पहुंचा देंगे!

ख़बर दार

खाट के ठाठ-बाठ

उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेसी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर ने 'खाट सभा' का नया तमाशा शुरू कर दिया है। देवरिया से शुरू हुई राहुल गांधी की किसान रैलियों में श्रोताओं के लिये हज़ारों की संख्या में खाट बिछा दी जाती हैं। नया चलन होने के कारण यह सब के लिये आकर्षण का केन्द्र रहीं। पहली सभा खत्म होने पर श्रोताओं ने खाट अपनी समझ कर घर ले जाना शुरू कर दिया। भाजपाइयों और सपाइयों ने इसकी खिल्ली उड़ाई जबकि कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जिनकी खाट थी वे ले गये तो क्या हुआ! राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि विजय माल्या जैसे पूंजीशाह देश का नौ हज़ार करोड़ लूट कर ले गये तब भाजपा की मोदी सरकार ने विरोध नहीं किया और अब किसानों को चोर लुटेरा कह रहे हैं। -मज़दूर मोर्चा' ने भाजपा सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इस विषय में और जानने की कोशिश की।

म.मो.-देहाती खाट के ठाठ-बाठ भी लौट आये। इस पर आपका क्या कहना है?

कांग्रेस-हमने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि किसान को खाट से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिये।

भाजपा-कांग्रेस के पास किसान को देने के लिये खाट के सिवाय और है भी क्या? मोदी जी ने डिजिटल इन्डिया का नया नारा दिया है जो देश के सबसे बड़े थैलीशाह मुकेश अम्बानी के भरोसे मुफ़्त टेलिफ़ोन सेवा के रूप में किसानों तक पहुंचेगा। बदले में अम्बानियों को लाखों करोड़ का बैंक कर्ज़ा, टैक्स माफ़ी व काला धन डकारने की छूट बदस्तूर जारी रहेगी। इससे बड़ी किसान सेवा और कोई क्या कर सकता है।

सपा-हमारे युवा नेता अखिलेश यादव जी ने सभी किसानों को मुफ़्त में स्मार्ट फ़ोन देने का वायदा कर दिया है। आत्महत्या करने वाले किसानों के लिये इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है?

म.मो.-किसानों ने जो खाट लुटाई की उस पर आपको क्या कहना है?

कांग्रेस-हमने 60 साल के शासनकाल में यही परम्परा तो डाली है कि जिसके हाथ जो लग जाये वह लूट लो। बेचारे किसानों ने भी तो इसी परम्परा का ही तो पालन किया।

भाजपा-सपा, बसपा के लम्बे शासन काल में किसान इतना ग़रीब हो गया है कि उसे खाट लूटनी पड़ रही है। हमारा राज आने दो हम जन-धन योजना में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि गांव का व्यक्ति भी बैंकों को लूट सकेगा। जब हमने अडानियों-अम्बानियों को हज़ारों-लाखों करोड़ बैंकों से लूटने की छूट दे रखी है तो किसान को कुछ हज़ार लूटने की छूट देने में क्या हर्ज़ है?

सपा-हमारी पार्टी ने यादव बहुल गांव वालों को सरकारी योजनाओं को ही नहीं बल्कि घरों व सड़कों पर जाकर लूटपाट की खुली छूट दे रखी है। इसी सुविधा को हम अन्य बाहुबली समुदायों के लिये खोल देंगे, बस एक बार और चुन कर आने की देर है।

सड़कों के नाम पर हड़पने को नगर निगम ने मांगे 120 करोड़

फ़रीदाबाद (म.मो.) सड़कों की मुरम्मत के लिये नगर निगम ने हरियाणा सरकार से 120 करोड़ रुपये की मांग की है। दरअसल इस तरह की मांग न तो पहली बार की गयी है ओर न ही आखिरी बार। यह तो हर रोज़ का तमाशा है। सड़कें बनाई ही इस तरह जाती हैं कि वे जल्दी टूटे और फ़िर दोबारा से मुरम्मत का बजट बन कर आये। कोई यह पूछने वाला नहीं है कि एक बार की बनी सड़क साल भर भी क्यों नहीं टिकती। सड़क बनाने से पूर्व जल निकासी का उचित प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता? जाहिर है पूछने की हैसियत रखने वाले खुद सड़कों के इस घोटाले में शामिल हैं।

सड़कों की मुरम्मत का जो बजट बनाया गया है वह होता है शहर भर की तमाम सड़कों का, परन्तु बजट आने पर काम होता है केवल चन्द गिनी-चुनी सड़कों पर ही शेष बजट दांयें-बांये करके डकार लिया जाता है। वैसे भी सड़कों का या कोई भी काम शुरू करने से पहले जरूरी होता है निमग कर्मचारियों का वेतन। कोई भी बजट आये, किसी भी काम के लिये आये, सर्वप्रथम तो उसमें से वेतन की ही अदायगी होती है।

सड़क व सीवर, दो ऐसे मद हैं जिसके नाम पर निगम के इन्जीनीयर जितना मर्जी बजट मांग लें, जनता के भारी दबाव के चलते यह बजट मिलता ही है। मजे की बात यह है कि बजट मिलता रहता है, खर्च होता रहता है और समस्या भी जस की तस बनी रहती है। शहर की कुछ प्रमुख सड़कें-नीलम-बाटा, बाटा-हार्डवेयर, हार्डवेयर-बी के चौक-नीलम चौक आदि पर निगम गत 15 वर्षों में इतना पैसा खर्च कर चुका है जितने में इन सड़कों में सोने की ईंटें लगाई जा सकती थी। इतना भारी-भरकम खर्च करने के बावजूद भी इन प्रमुख सड़कों की हालत दयनीय है।

हालात को देखते हुए कहा कहा जा सकता है कि निगम को 120 करोड़ क्या 120 हज़ार करोड़ भी दे दिये जायें तो भी सड़कों की हालत तो ऐसी ही रहने वाली है। हां यदि कोई ढंग से हिसाब लेने वाला आ जाये तो ये सड़कें 20 करोड़ में भी चुस्त-दुरूस्त हो सकती है।